



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34632

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए सं. - 2315 वर्ष 2026

केशव कुमार और 4 अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता	: आदित्य प्रकाश वर्मा, रंजना वर्मा, शैलेश वर्मा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं.- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचीओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव की बात सुनी गई।
2. श्री आर.एस. उमराव ने बार में बयान दिया है कि उन्हें सभी निर्देश अच्छे से पता हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और उनका कोई शपथपत्र दाखिल करने का कोई इरादा नहीं है और रिट याचिका पर अभिलेख में मौजूद प्रपत्र के आधार पर फैसला किया जाएगा। पक्षकारों की सहमति से, इस स्तर पर रिट याचिका पर फैसला किया जा रहा है।
3. रिट याची का वाद यह है कि रिट याची भूतपूर्व सैनिक हैं, जिसका विवरण रिट याचिका के पैरा 9 में दी गई हैं, जो नीचे दिया गया है:-

"9. यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि याची संख्या 1, 22.02.1996 को सेना में भर्ती हुए थे और 28.02.2015 को 'सिपाही' के पद से सेवामुक्त हुए थे; याची संख्या 2, 17.07.1999 को सेना में भर्ती हुए थे और 30.09.2017 को 'हवलदार' के पद से सेवामुक्त हुए थे; याची संख्या 3, 11.11.2002 को सेना में भर्ती हुए थे और 30.11.2019 को 'सिपाही एसीपी-II' के पद से सेवामुक्त हुए थे; याची संख्या 4, 09.10.2001 को सेना में भर्ती हुए थे और 30.09.2019 को 'नायक

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एसीपी-1' के पद से सेवामुक्त हुए थे; याची संख्या 5, 19.04.2002 को सेना में भर्ती हुए थे और 31.12.2019 को 'नायक' के पद से सेवामुक्त हुए थे। याचीओं की सेना में पिछली सेवा से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जा रही हैं और इस रिट याचिका के 'अनुलग्नक संख्या 5' के रूप में चिह्नित की गई हैं।"

4. रिट याची के अनुसार, उन्होंने अक्टूबर, 2018 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए भर्ती प्रक्रिया के अनुसार सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयन में भाग लिया था, रिट याचीगण को आयोजित एक परीक्षा के अनुसार चुना गया था, चयन सूची मार्च, 2020 में प्रकाशित हुई और उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, हालांकि, अब सेना में पूर्ववर्ती कार्य के संदर्भ में उनके वेतन संरक्षण पर इस बहाने विचार नहीं किया जा रहा है कि 23.12.2020 का एक शासनादेश है। रिट याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के रिट-ए संख्या 10689/2024 (सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य) के एक फैसले की सहायता लेना चाहा है, जिसमें 23.12.2020 के शासनादेश में निर्दिष्ट कट ऑफ तिथि के संबंध में वर्गीकरण को नकार दिया गया उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अब अन्तरा-न्यायालय अपील विशेष अपील संख्या 1233/2025 (यूपी राज्य और 3 अन्य बनाम विनय और 3 अन्य) होने के कारण, राज्य सरकार की अपील खारिज होने के साथ ही मामला कवर हो गया है।

5. श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामला सीता राम शर्मा (पूर्वोक्त) के निर्णय के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष अपीलीय पीठ द्वारा पुष्टि की गई है।

6. मैंने बार में की गई इस बात को सुना है और अभिलेख को पढ़ा है।

7. तथ्य वाद-बिन्दु में नहीं हैं। यह वाद-बिन्दु नहीं है कि रिट याची भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। सीता राम शर्मा (पूर्वोक्त) में ऐसा लिखा है।-

"1. याचीओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की गई ऊपर दी गई रिट याचिका के ज़रिए, यूपी. सिविल पुलिस 2018 में कांस्टेबल जीडी के लिए चुने गए याची, भूतपूर्व सैनिक के तौर पर उनकी अन्तिम वेतन के हिसाब से वेतन संरक्षण न देने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के प्रत्यर्थी के भेदभाव वाले रवैये से नाराज़ हैं। सभी याची भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में चुने गए और नियुक्त किए गए थे और उनका कहना है कि अगर एक ही चयन के परिणाम में, चुने गए लोगों को अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण के लिए चार बैच में भेजा जाता है, तो राज्य का पहले बैच के ट्रेनी को वेतन संरक्षण देना और दूसरे ट्रेनी को सिर्फ़ इस आधार पर मना करना सही नहीं है कि शासनादेश में भूतपूर्व सैनिक को अगली तारीख से वेतन संरक्षण न देने का फैसला किया गया था।

3. यह बताया गया है कि चयन होने के बाद चुने गए अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के उस समय के हालात की वजह से निदेशक पुलिस प्रशिक्षण, यूपी ने 25 जुलाई, 2020 के अपने आदेश के ज़रिए चुने गए अभ्यर्थी को चार बैच में बाँट दिया, जिन्हें अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग समय के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना था। पहले बैच को अगस्त, 2020 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, दूसरे बैच को मार्च, 2021 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, तीसरे बैच को अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और आखिरी और चौथे बैच को मई, 2022 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

4. इस न्यायालय में याचीगण का दावा है कि उन्हें दूसरे बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जो मार्च, 2021 से शुरू हुआ और सितंबर, 2021 तक छह महीने तक चला। जब पहला बैच अपनी प्रशिक्षण पूरी कर रहा था, तो 23 दिसंबर, 2020 के शासनादेश से पहले उनके लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया था, जिस तारीख को शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि चुने गए लोगों, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, को अब कोई वेतन संरक्षण नहीं दिया जाएगा। शासनादेश में आगे कहा गया कि यह तुरंत लागू होगा। शासनादेश का संबंधित पैराग्राफ, जैसा कि पैराग्राफ 22 में है, नीचे दिया गया है:

"उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(1) सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनर्योजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे पुनर्योजित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षाणीय (इग्नोर्ड) है, का वेतन पुनर्योजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षाणीय (इग्नोर्ड) नहीं है, उनमें पुनर्योजन पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु-

(1) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ई) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्योजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ईई) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अन्तिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनर्योजन के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षाणीय (इग्नोर्ड) नहीं है, घटा दिया जायेगा।

(4)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानेवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

4- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरुद्घटित नहीं किये जायेंगे।"

5. याचीगण के अधिवक्ता ने दलील दी कि पहले बैच ने जनवरी, 2021 में अपनी प्रशिक्षण पूरी कर ली थी, उसके बाद उन्हें वेतन संरक्षण दिया गया था और उदाहरण के लिए, कुलदीप सिंह, नए चुने गए कांस्टेबल, पीएनओ सं. 202641386, तारीख 24 जनवरी, 2024 का वेतन निर्धारण अभिलेख में लाया गया है। यह दलील दी गई कि पहले बैच को फायदा दिए जाने के बाद, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच में चुने गए अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक भी थे, को यह फायदा नहीं दिया गया।

6. ऊपर बताई गई ये बातें रिट याचिका के पैराग्राफ 14 में उठाई गई हैं, जिसमें कई दूसरे कांस्टेबलों का विवरण है जिन्हें अन्तिम वेतन संरक्षण का फायदा मिला था, और वे खुद को भूतपूर्व सैनिक बता रहे थे। पैराग्राफ 14 के जवाब में प्रति शपथपत्र में, पैराग्राफ 16 के हिसाब से, यह कहा गया है:

"रिट याचिका के पैराग्राफ सं. 14 का विवरण इस हद तक माना जाता है कि 11.10.2020 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल कुलदीप सिंह पीएनओ सं. 202641386 के नियुक्ति के समय, 26.8.1977 और 18.5.1983 का शासनादेश लागू था, अभी, भूतपूर्व सैनिक को राज्य सरकार की सेवा में फिर से नियुक्त करने का 23.12.2020 का शासनादेश लागू है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह आदेश तुरंत लागू होगा, यानी जिन भूतपूर्व सैनिक को शासनादेश जारी होने की तारीख को या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त किया गया है, वे इस आदेश के तहत आएंगे।"

7. ऊपर बताए गए प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ 14 में कही गई बातों को सिर्फ पढ़ने से पता चलता है कि कुलदीप सिंह को पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें 11.10.2020 को नियुक्ति दिया गया था, जब 26.8.1977 और 18.5.1983 के शासनादेश लागू थे और इसलिए उन्हें वेतन संरक्षण का यह फायदा दिया गया था।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लेकिन, भूतपूर्व सैनिक की पुनः नियुक्ति के संबंध में 23.12.2020 के शासनादेश के लागू होने पर, उन्हें अपनी पिछली जगह के वेतन संरक्षण का हकदार नहीं माना गया और इसलिए मौजूदा याची को ऐसा कोई फायदा नहीं दिया जा सका। इस तरह, यह माना जाता है कि याचीगण को सिर्फ इसलिए वेतन संरक्षण नहीं दिया गया क्योंकि उनकी प्रशिक्षण पहले बैच के बाद पूरी हुई थी, जबकि याचीगण भी पहले बैच की तरह ट्रेनी थे जो बाद में कांस्टेबल बन गए। इस तरह सभी नियुक्ति वर्ष 2018 में हुए चयन और भर्ती के आधार पर चुने गए थे और इसलिए उन्होंने वेतन-समानता का दावा किया।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने, वेतन सुरक्षा से इनकार करने वाले शासनादेश के तहत लिए गए रुख का बचाव करने की कोशिश की है, और इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया है - यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अनिल प्रसाद (2022 5 एससीसी 461) - जिसमें पूर्व सैनिकों को वेतन सुरक्षा का लाभ देने से इनकार करने वाले केंद्र सरकार के नियमों को सही ठहराया गया था। इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि वेतन सुरक्षा लाभ देने से इनकार करने के सरकारी कदम में कोई ऐसी कमी नहीं पाई जा सकती, जिसके आधार पर इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण या अनुचित ठहराया जा सके। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस फैसले के पैराग्राफ 4.5 का हवाला दिया है, जो इस प्रकार है:

"5.4 इसलिए, सरकारी सेवा में प्रत्यर्थी का वेतन निर्धारण सीसीएस आदेश 1986 के पैरा 8 के बिल्कुल अनुरूप था। पैरा 8 में यह प्रावधान नहीं है कि सरकारी सेवाओं में दोबारा नौकरी मिलने पर, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी अपनी पिछली प्राप्त वेतन के बराबर अपना मूल वेतन निर्धारित करवाने का हकदार होगा। ऐसा मानना सीसीएस आदेश के पैरा 8 का उल्लंघन होगा। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी और निर्णय देकर गंभीर त्रुटि की है कि सरकारी सेवा में दोबारा नियुक्त होने पर, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी सशस्त्र बल कर्मी के रूप में अपने पिछली प्राप्त वेतन का हकदार होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, सीसीएस आदेश, 1986 के पैरा 8 के विपरीत होने के कारण, मान्य नहीं है।"

9. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि इस याचिका में, शासनादेश में निहित उस प्रासंगिक



प्रावधान को चुनौती देने के बजाय—जो पूर्व-सैनिकों को सरकारी गैर-रक्षा संस्थानों में दोबारा नौकरी मिलने पर वेतन सुरक्षा का लाभ देने से इनकार करता है—याचीओं के साथ हो रहे भेदभाव को अधिक चुनौती दी गई है।

10. याची के अधिवक्ता ने मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 0 एससी 764 मामले में दिए गए फैसले पर जोर दिया है, और यह तर्क दिया है कि सिर्फ इसलिए कि काउंसलिंग नहीं हुई या उसमें देरी हो गई, एक ही चयन प्रक्रिया के तहत समान और एक जैसी स्थिति वाले शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था। उन्होंने फैसले के पैराग्राफ 15 की सहायता लिया है, जो इस प्रकार है:

"अपीलकर्ता का मामला राकेश गौर (पूर्वोक्त) के मामले से ज्यादा मिलता-जुलता था, जिसने 05.11.2009 को दाखिला लिया था। इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए हमारी साफ़ राय है कि डिवीज़न बेंच ने इस मामले के तथ्यों पर अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त) और राकेश गौर (पूर्वोक्त) के फैसले के तर्क को लागू करने के बजाय दिनेश चंद्र दामोर (पूर्वोक्त) के मामले को लागू करने में गलती की। जैसा कि अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त) में कहा गया था, 2009-10 के शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला लेने वाले छात्रों के एक समरूप समूह के बीच आपस में भेदभाव करना अनुचित होगा। जैसा कि उसमें बताया गया था, ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसलिंग के पहले दौर में दाखिला लेने वाले छात्र, ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक होने पर भी, योग्य माने जाएँ, जबकि काउंसलिंग के बाद के दौर में दाखिला लेने वाले अन्य छात्र योग्य न माने जाएँ। इसी तर्क के आधार पर राकेश गौर (पूर्वोक्त) को राहत दी गई थी। राकेश गौर (पूर्वोक्त) का मामला अपीलकर्ता के मामले के बिल्कुल समान स्थिति वाला मामला था। जो नियम एक पर लागू होता है, वही दूसरे पर भी लागू होना चाहिए।"

11. इस प्रकार, इस याचिका में इस न्यायालय द्वारा जिस एकमात्र प्रश्न का निर्धारण किया जाना है, वह यह है कि क्या उसी चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए उन उम्मीदवारों को दी गई वेतन सुरक्षा जिन्हें पहले प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था—उन याचीओं को देने से मना किया जा सकता है, जिन्होंने बाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण प्रशिक्षण को चार अलग-अलग बैचों में आयोजित किया जा रहा था। प्रत्यर्थियों की ओर से इस बात से कोई इनकार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं है कि सभी याची, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए दूसरे बैच में भेजा गया था, उसी विज्ञापन के तहत और उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत यू.पी. पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए चुने गए थे। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो चुने हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए की जाती है; और एक बार जब उम्मीदवार का चयन हो जाता है, तो अंततः प्रकाशित और घोषित 'चयन सूची' में शामिल होने के परिणामस्वरूप ही प्रशिक्षण होता है। इस प्रकार, एक बार जब उम्मीदवारों को नियुक्ति के उद्देश्य से प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु चयन सूची तैयार हो गई, तो चयन का कोई और चरण शेष नहीं रह गया था। इसलिए, यह चुने हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अतः, न्यायालय के सुविचारित मत में, यदि प्रत्यर्थियों ने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षुओं को अलग-अलग समूहों या बैचों में बांटकर अलग-अलग तारीखों पर प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्णय लिया था—और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर ऐसे प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दी गई थी—तो सेवा-संबंधी लाभों (जैसे वेतनमान, भत्ते और अन्य परिलब्धियाँ जो उस पद के लिए अनुमेय हैं) के मामले में उनके साथ निश्चित रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि वरिष्ठता के मामले में भी, केवल चयन सूची का ही पालन किया जाना चाहिए। मनीलाल (उपर्युक्त) के मामले में उद्धृत निर्णय, याचीओं के इस मामले पर पूरी तरह से लागू होता है। उस निर्णय में न्यायालय ने यह माना था कि एक समरूप समूह के सदस्यों के बीच आपस में किया गया भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, उसी चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए सभी उम्मीदवार मिलकर एक समरूप समूह का निर्माण करते हैं, और उनकी नियुक्ति केवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक परिणाम मात्र है (बशर्ते कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अस्वीकृत न किया गया हो)। एक बार जब किसी समरूप समूह को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है, तो उस समूह के सभी सदस्यों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

12. प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले क्लस्टर या ग्रुप के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि समान स्थिति वाले कर्मचारियों को लाभ देने के उद्देश्य से यह कोई उचित वर्गीकरण नहीं होगा। समानता का एक स्थापित नियम यह है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया



जा सकता, और समान स्थिति वाले लोगों के साथ वेतन समानता और सेवा लाभ देने के मामले में समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

13. फिरंगी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2011) 2 यूपीएलबीईसी 987 के मामले में, इस न्यायालय ने यह माना है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने में की गई गलती के कारण, याचीओं को किसी भी नुकसानदायक स्थिति में नहीं डाला जा सकता। हालाँकि यह मामला नियमितीकरण से संबंधित था, लेकिन चूंकि प्रबंधन ने देरी से नियुक्ति आदेश जारी किए थे—और यहाँ तक कि नियमितीकरण नियमों की कट-ऑफ तारीख के बाद भी—इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार किया गया और उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया गया। इस निर्णय का आगे चलकर महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (रिट ए संख्या 55606, 2008) के मामले में भी पालन किया गया, जिसका निर्णय 19.12.2019 को दिया गया था। इस मामले में, एक ही विज्ञापन के तहत चयनित सभी आवेदकों को एक समरूप समूह माना गया, ताकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सके; इसका कारण यह था कि विज्ञापन और चयन की प्रक्रिया पुरानी पेंशन योजना को समाप्त किए जाने से पहले ही पूरी हो चुकी थी, भले ही नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए गए थे।

14. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण को देखते हुए, जहाँ मुझे शासनादेश के क्रियान्वयन में, जहाँ तक पूर्व-सैनिकों को वेतन सुरक्षा से वंचित करने का प्रश्न है, कोई भी भेदभावपूर्ण बात नज़र नहीं आती; वहीं यह शासनादेश केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा जिनमें उम्मीदवारों का चयन इस आदेश के जारी होने के बाद हुआ था। वे सभी उम्मीदवार जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है और जिन्हें अंततः नियुक्ति दी जानी है, वे एक समरूप समूह का हिस्सा माने जाएँगे और उन्हें वेतन सुरक्षा सहित वे सभी लाभ प्राप्त होंगे; तथा शासनादेश उनके दावों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

15. जहाँ तक विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का प्रश्न है, उसमें प्रतिपादित विधि (कानून) के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि मेरा भी यही मत है कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए शासनादेश को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह माना जाता है कि यह आदेश वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचीओं को 'अंतिम वेतन सुरक्षा' का लाभ प्रदान करें, जैसा कि यू.पी. पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के तहत प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिया गया था। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा और याचीओं को परिणामी लाभ प्रदान किया जाएगा।"

8. इसके अलावा, **यू.पी. राज्य और 3 अन्य बनाम विनय और अन्य (पूर्वोक्त)** मामले में यह इस प्रकार है:-

"1. सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से, श्री तेज भानु पांडे (स्थायी अधिवक्ता) की सहायता से, श्री मनीष गोयल (अपर महाधिवक्ता) को सुना गया; तथा संबंधित अपीलों में प्रत्यर्थियों की ओर से, श्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और श्री आदित्य प्रकाश वर्मा (अधिवक्ता) की सहायता से, श्री आर.के. ओझा (वरिष्ठ अधिवक्ता) को सुना गया।"

2. ये सभी अपीलें 09.04.2025 को माननीय एकल-न्यायाधीश द्वारा पारित एक साझा निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं। यह निर्णय उन संबंधित रिट याचिकाओं के संबंध में दिया गया था जिन्हें रिट ए संख्या 10689/2024 (सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) के साथ ही निपटाया गया था। इस निर्णय के तहत, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया था, और अपीलकर्ता संख्या 3 (वर्तमान मामले में) को निर्देश दिया गया था कि वे याचीओं को 'अंतिम वेतन सुरक्षा' का लाभ प्रदान करें। यह लाभ इसलिए देने को कहा गया था क्योंकि यू.पी. पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के तहत प्रशिक्षुओं के पहले बैच को यह लाभ पहले ही दिया जा चुका था। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर उचित आदेश पारित किया जाए और परिणामी लाभ प्रदान किया जाए।

3. अपीलकर्ता (उत्तर प्रदेश राज्य) ने इन सभी अपीलों में एक ही प्रकार का मुद्दा उठाया है; अतः, इन सभी अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई और अब इन सभी का निर्णय इस साझा आदेश के माध्यम से किया जा रहा है। इन सभी अपीलों में निहित मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों को, उनके नियुक्ति पत्रों

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की अलग-अलग तिथियों और उनके प्रशिक्षण के लिए निर्धारित अलग-अलग तिथियों के आधार पर, एक अलग वर्ग के रूप में माना जा सकता है। प्रत्येक अपील में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित तथ्यात्मक विवरण—जैसे कि उनकी पिछली सेवा का विवरण, नियुक्ति पत्र की तिथि, और पत्र में उनके प्रशिक्षण की अवधि के लिए उल्लिखित तिथि—भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

4. सुविधा के लिए, तथ्यात्मक विवरण विशेष अपील संख्या 1240/2025 से लिए जा रहे हैं, क्योंकि माननीय एकल-न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.04.2025 को पारित निर्णय और आदेश में यही मुख्य याचिका थी; हालाँकि, इस वर्तमान साझा आदेश का परिणाम सभी संबंधित मामलों पर लागू होगा। एकमात्र तथ्यात्मक अंतर संबंधित अपीलों में प्रत्यर्थियों/उम्मीदवारों की संख्या का है।

5. विशेष अपील के मामलों के इस समेकित समूह के अभिलेख की जाँच करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ सभी प्रत्यर्थी भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्य हैं, जो अलग-अलग समय पर विभिन्न रेजिमेंटों में भर्ती हुए थे। आगे यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रत्यर्थी को उसकी सेवा अवधि पूरी होने पर सेवामुक्त या सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उनकी व्यक्तिगत सेवा अवधियों में अंतर होने के बावजूद, इन सभी मामलों में एक साझा तथ्य यह उभरकर आता है कि सभी प्रत्यर्थियों ने अपनी सैन्य सेवा पूरी कर ली थी और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनका चयन हुआ तथा उन्होंने उसी चयन सूची में अपना स्थान सुरक्षित किया, जो अपीलों के इस समूह का विषय है।

6. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अक्टूबर 2018 की सीधी भर्ती के तहत तैयार की गई चयन सूची से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई थी, क्योंकि प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, राज्य के लिए यह ज़रूरी हो गया था कि वह चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से आयोजित करे; इसलिए, उम्मीदवारों के संबंधित प्रशिक्षण चरणों के अनुसार अलग-अलग तारीखों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि यू.पी. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने दिनांक 25.07.2020 के आदेश के माध्यम से, चयनित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उम्मीदवारों को अलग-अलग तारीखों और अलग-अलग अवधियों के प्रशिक्षण के लिए चार बैचों में विभाजित किया। इसके बाद, पहले बैच का प्रशिक्षण अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए शुरू हुआ। दूसरा बैच मार्च 2021 में छह महीने के लिए शुरू हुआ। तीसरा बैच अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए शुरू हुआ, और चौथा बैच मई 2022 में शुरू हुआ, जो भी छह महीने की अवधि के लिए था।

7. विद्वान अपर महाधिवक्ता के अनुसार, राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए, अलग-अलग समय पर और अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग वेतन संरचना निर्धारित करने का पूरा अधिकार रखता था; और अपीलकर्ता राज्य अन्य बैचों के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने में भी पूरी तरह से उचित था, भले ही उन्हें वह समान वेतन सुरक्षा प्रदान न की गई हो, जो पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले सदस्यों को दी गई थी। यह भी दलील दी गई है कि चयन सूची को सभी उद्देश्यों के लिए एक समरूप वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है, और राज्य द्वारा बाद के तीन बैचों को पहले बैच से एक अलग श्रेणी में रखना पूरी तरह से उचित है, क्योंकि पहले बैच ने अन्य बैचों की तुलना में अपना प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया था।

8. यह निर्विवाद है कि पहले बैच को, जिसने जनवरी 2021 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया था, वेतन सुरक्षा का लाभ दिया गया था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क यह है कि विभिन्न बैचों से संबंधित उम्मीदवारों के साथ किया गया अलग व्यवहार—जिन्हें एक ही सूची से चुना गया है—भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुमेय दायरे के भीतर है; और इसलिए, राज्य उन चार बैचों के लिए अलग-अलग वेतन संरचनाएं निर्धारित करने का हकदार है, जिन्होंने अलग-अलग समय पर अपना प्रशिक्षण शुरू किया था।

9. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने 'उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015' के नियम 19 की सहायता लिया है, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

नियम - 19. प्रशिक्षण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(1) (ए) नियम 15 और 16 के तहत कांस्टेबल के पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को, विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों पर 'पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नियमावली' के प्रावधान प्रभावी होंगे। यदि बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसका चयन/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(बी) बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण होने वाले कैडेटों की पुनः परीक्षा, पूरक प्रशिक्षण के बाद विभाग प्रमुख द्वारा आयोजित की जाएगी। पूरक प्रशिक्षण के बाद आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) नियम 17 के तहत पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को, विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा।

10. माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता का तर्क है कि कांस्टेबल के पद के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसे उत्तीर्ण करें; ऐसा न कर पाने की स्थिति में, उनका चयन रद्द किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम अधिकारियों को पूरक प्रशिक्षण और पुनः परीक्षा आयोजित करने का अधिकार भी देते हैं, और उन उम्मीदवारों की सेवाएँ समाप्त करने का भी अधिकार देते हैं जो इसके बाद भी असफल रहते हैं; इसी प्रकार, पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों के लिए भी निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। इसलिए, जब तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता, तब तक राज्य को वेतन संरचना में बदलाव करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि राज्य की कार्यवाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वह आगे कहते हैं कि प्रत्यर्थियों का चयन 2018 में सिविल पुलिस और पीएसी में कांस्टेबल के पदों के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत हुआ था, और मार्च 2020 में घोषित नतीजों में उन्हें विधिवत पूर्व-सैनिक श्रेणी में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रखा गया था। वह आगे तर्क देते हैं कि 23.12.2020 का शासनादेश—जहाँ तक यह कहता है कि उस तारीख के बाद की गई सभी नियुक्तियों को वेतन सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा—अस्वीकार्य है, क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है; खासकर तब, जब सभी उम्मीदवारों को एक ही चयन सूची में रखा गया है। आगे यह भी कहा गया है कि पहले चरण में नियुक्त उम्मीदवारों को वेतन सुरक्षा का लाभ दिया गया था, और इस तथ्य को राज्य सरकार ने लगातार स्वीकार किया है।

12. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 2024 एससी 4404, की सहायता लिया हैं, और कहते हैं कि एक ही चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए सभी उम्मीदवार एक ही समरूप समूह का हिस्सा होंगे, और इस समरूप समूह के सदस्यों के बीच आपस में भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वह महेश नारायण और अन्य उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट ए सं.. 55606 of 2008, की भी सहायता लिया हैं, जिसका फैसला इस उच्च न्यायालय ने 19.12.2019 को सुनाया था। उपरोक्त फैसलों की सहायता से, विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि इस तरह के अलग व्यवहार को केवल किसी 'समझने योग्य अंतर' के आधार पर ही सही ठहराया जा सकता है, जो इन मामलों के तथ्यों में मौजूद नहीं है।

13. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रशिक्षण के संबंध में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का जवाब दिया, यानी यू.पी. पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियम, 2015 का नियम 19। उनके अनुसार, विद्वान एकल-न्यायाधीश ने सही ही यह टिप्पणी की है कि प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों के लिए एक प्रक्रिया है और एक बार जब नियुक्ति के उद्देश्य से प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार हो जाती है, तो चयन का कोई और चरण शेष नहीं रह जाता। उन्होंने आगे यू.पी. पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियम, 2015 के नियम 18 का हवाला दिया है, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

नियम - 18. नियुक्ति

(1) नियम 15 और 16 के प्रावधानों के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों के नामों को उसी क्रम में लेकर नियुक्ति करेगा जिस क्रम में वे नियम 15 के खंड (जी) के तहत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तैयार की गई सूची में हैं। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा, जिसमें यह निर्देश होगा कि वे पत्र जारी होने की तारीख के एक महीने के भीतर, या नियुक्ति पत्र में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख तक, सेवा/प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करें। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसका चयन/नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के शुरू होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और उस पद पर काम कर रहा हो, उसे इन नियमों के तहत असल में नियुक्त किया हुआ माना जाएगा।

(2) अगर नियम 17 के तहत किसी एक चयन के संबंध में एक से ज्यादा नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं, तो एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें चयन में तय की गई ज्योष्ठता के क्रम में या, जैसा भी मामला हो, उस कैडर में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, लोगों के नाम बताए जाएंगे:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के शुरू होने से पहले सर्विस में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और उस पद पर काम कर रहा हो, उसे इन नियमों के तहत असल में नियुक्त किया हुआ माना जाएगा और ऐसी असल नियुक्ति इन नियमों के तहत की गई मानी जाएगी।

14. ऊपर बताए गए प्रोविज़न पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने कहा कि नियम 18 में नियम 15 और 16 के तहत चुने गए अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने का विचार है, और उसके बाद ही नियम 19 ऐसे अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने की ज़रूरत बताता है। प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने कहा कि नियमों की स्कीम साफ़ तौर पर दिखाती है कि नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण से पहले दिया जाता है, और इसलिए, प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता, जैसा कि सिंगल जज ने सही कहा है, क्योंकि प्रशिक्षण नियुक्ति के बाद होनी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. हमने अपीलकर्ताओं/राज्य के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख की जाँच की है, जिसमें विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्ष भी शामिल हैं। कुछ बुनियादी तथ्य आक्षेपित नहीं हैं। सभी उम्मीदवारों का चयन-भले ही उन्हें बाद में प्रशिक्षण के लिए किसी भी बैच में भेजा गया हो-अक्टूबर 2018 में जारी किए गए एक ही भर्ती विज्ञापन के आधार पर किया गया था। चयन सूची एक ही थी, चयन प्रक्रिया एक समान थी, और नियुक्तियाँ उसी भर्ती प्रक्रिया से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थीं।

16. अभिलेख की सामान्य जाँच से यह प्रतीत होता है कि सभी नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2018 की उसी सीधी भर्ती के तहत की गई नियुक्तियों से संबंधित हैं, जो एक ही विज्ञापन और चयन प्रक्रिया से शुरू हुई थी। किसी भी पक्ष का यह भी दावा नहीं है कि जिस विज्ञापन के आधार पर चयन सूची तैयार की गई थी, उसमें किसी ऐसे वर्गीकरण या श्रेणी-वार अंतर का प्रावधान था। इसके अलावा, राज्य यह साबित नहीं कर पाया है कि उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए चार अलग-अलग चरणों में भेजने का निर्णय किसी तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित था।

17. ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, हमारा यह सुविचारित मत है कि चरणों में प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता केवल अपीलकर्ता राज्य के सामने मौजूद बुनियादी ढांचे की सीमाओं और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपात स्थितियों के कारण पड़ी थी, न कि चयनित सूची में शामिल उम्मीदवारों के बीच किसी समझ में आने वाले अंतर के कारण। इसलिए, बाद के बैचों में प्रशिक्षण के लिए रखे गए उम्मीदवारों को उनके अधिकारों से वंचित करना घोर मनमाना है और इसमें पक्षपातपूर्ण भेदभाव का दोष है।

18. माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता के तर्क का पूरा आधार यह है कि चरणों में किए गए प्रशिक्षण ने ही चार अलग-अलग श्रेणियाँ बना दीं, जिससे राज्य को अलग-अलग वेतन संरचनाएं निर्धारित करने और बाद के बैचों का हिस्सा रहे प्रत्यर्थियों को वेतन सुरक्षा देने से रोकने का अवसर मिल गया।

19. यद्यपि यह न्यायालय महामारी से संबंधित आपात स्थितियों और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को स्वीकार करता है, लेकिन ऐसी बाहरी और अस्थायी प्रशासनिक मजबूरियाँ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एक ही वर्ग के उम्मीदवारों के बीच अलग-अलग व्यवहार को उचित नहीं ठहरा सकतीं। अनुच्छेद 14 के तहत अनुमेय वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाली कानूनी स्थिति इतनी सुस्थापित है कि उसे और विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है; और जब स्थापित मापदंडों पर इसकी जांच की जाती है, तो अपीलकर्ता राज्य द्वारा दिया गया औचित्य जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

20. बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 एससीसी 1 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित या भ्रामक नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, वर्गीकरण एक 'समझने योग्य अंतर' पर आधारित होना चाहिए; क्योंकि अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को मनमाने भेदभाव से बचाना है—चाहे वह भेदभाव किसी कानून के स्पष्ट प्रावधानों के कारण हो, या फिर उस कानून के अनुचित प्रयोग के कारण। कोई भी वर्गीकरण एक ऐसे 'समझने योग्य अंतर' पर आधारित होना चाहिए जिसका, उस वर्गीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ, एक तार्किक संबंध हो; यदि ऐसा नहीं होता, तो ऐसा वर्गीकरण 'अस्वीकार्य भेदभाव' की श्रेणी में आ जाता है।

21. सीधी भर्ती क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1990) 2 एससीसी 715 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जो उम्मीदवार एक ही भर्ती अधिसूचना और चयन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, वे सेवा-संबंधी लाभों के उद्देश्य से एक ही वर्ग का निर्माण करते हैं। वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में, शीर्ष न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि—एक बार जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति नियमों के अनुसार किसी पद पर हो जाती है, तो उसकी वरिष्ठता की गणना उसकी 'नियुक्ति की तिथि' से की जानी चाहिए, न कि उसकी 'स्थायीकरण तिथि' से। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए, प्रशिक्षण की समाप्ति को—एक ही चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों के बीच कोई 'उप-वर्ग' निर्मित करने हेतु विचारणीय आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22. अपीलकर्ताओं ने किसी ऐसे वैधानिक नियम की ओर इशारा नहीं किया है जो राज्य को वेतन निर्धारण या वेतन सुरक्षा के उद्देश्य से, एक चयन सूची के भीतर उप-श्रेणियाँ बनाने का अधिकार देता हो। वास्तव में, राज्य का अपना ही यह रुख है कि प्रशिक्षण के लिए चरणबद्ध रूप से भेजना केवल प्रशासनिक आवश्यकता के कारण ही किया गया था। प्रशासनिक आवश्यकता, भले ही वह सद्भावनापूर्ण हो, उसे अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक रूप से अनुमेय विभेदक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ऐसे किसी तरीके की अनुमति देने से राज्य मनमाने या आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर एक समान अधिकारों को खंडित करने में सक्षम हो जाएगा, एक ऐसी प्रथा जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार अस्वीकृत किया है।

23. इसलिए, माननीय एकल-न्यायाधीश का यह निर्णय सही था कि प्रत्यर्थियों और अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को, जिनका चयन अक्टूबर 2018 की उसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, वेतन सुरक्षा और सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता, जो प्रशिक्षण के लिए पहले भेजे गए उम्मीदवारों के पहले बैच को दिए गए थे। संवैधानिक मानकों के स्वतंत्र अनुप्रयोग के आधार पर, हमें माननीय एकल-न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

24. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हमारा यह मत है कि अपीलकर्ता राज्य द्वारा एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों के बीच किया गया विभेद—जो पूरी तरह से उस तारीख पर आधारित है जिस दिन उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था—भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए एक अस्वीकार्य वर्गीकरण है।

25. राज्य द्वारा पहले बैच को दी गई वेतन सुरक्षा और उससे जुड़ी वेतन संरचना का लाभ, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच के उम्मीदवारों से नहीं छीना जा सकता; क्योंकि वे भी उसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे और उन्हें भी उसी चयन सूची में शामिल किया गया था।

26. इसलिए, हमें विद्वान एकल-न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता। तदनुसार, विशेष अपीलों का यह बैच असफल घोषित किया जाता है और खारिज किया जाता है। विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थियों और अन्य सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को वेतन सुरक्षा और परिणामी लाभ देने के संबंध में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जारी निर्देश की पुष्टि की जाती है। राज्य इस आदेश की तारीख से बारह सप्ताह के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

27. यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निस्तारण किया जाता है।

9. तदनुसार, दिनांक 10.09.2023 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है, और मामले को संबंधित अधिकारियों के पास वापस भेजा जाता है, ताकि वे उपरोक्त निर्णय के अनुरूप दो महीने की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित कर सकें।

10. ऊपर बताई गई बातों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

17 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”